

(c) and (d) The Fertiliser consumption during 91-92, is estimated to be 127.28 lakh tonnes and during 92-93 it is expected to be 126.57 lakh tonnes. The percentage variation in the total consumption of fertiliser is marginal.

देश में वैदिक विद्यालयों का खोला जाना

*79 श्री राम नरेश यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने कितने वैदिक विद्यालय खोलने की अनुमति दी है और ये विद्यालय कौन-कौन से राज्य में खोले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा वैदिक विद्यालयों के संबंध में कोई समिति गठित की गई है या गठित किए जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार के पास ए सी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत वैदिक विद्यालय खोलने की अनुमति दी जाती है। तथापि, सरकार स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों और मौखिक परंपराओं के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना के तहत वैदिक विद्यालयों तथा अध्ययताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में नवोदय विद्यालय

*80 श्री गया सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में कुल कितने नवोदय विद्यालयों में शिक्षण कार्य आरंभ हो गया है तथा कितने विद्यालयों में शिक्षण कार्य अभी शुरू किया जाना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : बिहार के 27 नवोदय विद्यालयों में से 26 विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो गई है।

Demand of rice in the country

498. SHRI RAMNARAYAN GO-SWAMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are expecting increase in demand for rice in the country by the end of 1993;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether internal production rate at present will be sufficient to tide over the demands;

(d) if not, whether Government plan to increase rice production in the country in view on increased demand; and

(e) if so, what are the details thereof and by when the said plan is to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (e) The demand for Rice in 1993 is expected to be fully met by domestic production of Rice which is estimated to be 71.5 million tonnes during 1992-93.

A Centrally Sponsored Integrated Programme for Rice Development (IPRD) is already under implementation in 24 States for increasing production and productivity of Rice. Through this scheme, incentives are being provided to farmers for use of certified seeds, micro-nutrients, herbicides, pesticides, farm implements, etc., with a view to motivate them to adopt improved rice production technology. Besides, field demonstrations and training programmes are also organised through, the programme for effective transfer of improved rice production technology.